DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- हिन्दुस्तान --------------DATED-- नई दिल्ली, शनिवार, 28 मई 2022

हाईकोर्ट ने सरकार को प्रस्ताव पर विचार करने का आदेश दिया

मच्छरों का लार्वा मिला तो लग सकता है भारी जुर्माना

सख्ती

50 हजार रुपये तक हो सकती है जुर्माना राशि | 200 हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं डेंगू मामलों की रोकथाम के लिए

इमारतों में जाल लगाने पर विचार करें

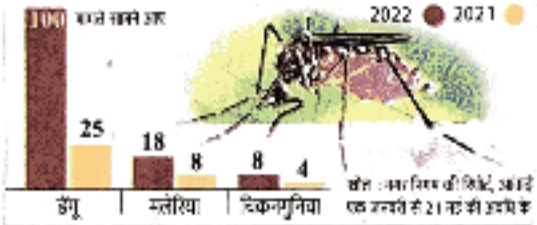

उच्च न्यायालय ने डीडीए को मच्छरों से बचने के लिए इमारतों में अनिवार्य रूप से जाल लगाने के बारे में विचार करने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पीठ ने एक अधिवक्ता के सुझाव पर डीडीए को यह निर्देश दिया है। अधिवक्ता ने इस बारे में कुछ दस्तावेज भी पेश किए। इन दस्तावेजों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी मुहैया कराया गया है।

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अगर आपके घर और आसपास बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पाया जाता है तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम 50 हजार रुपये तक हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपायों के तौर पर कानून में संशोधन करने और जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपये को बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा है कि मच्छरों का लार्वा मिलने पर मौके पर ही मोटा जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यदि लोगों के मन में कठोर कार्रवाई और मोटा जुर्माना लगाने का डर बैठ गया तो वे फिर अपने परिसरों में मच्छरों के प्रजनन को नहीं फैलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, पीठ ने कहा कि मच्छरों के प्रजनन और लार्वा को बढ़ावा देने में यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो जुर्माने की रकम 5000 तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब नई दिल्ली पालिका परिषद ने कहा कि लार्वा मिलने पर जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने पर विचार कर रहे हैं।

परिषद ने कहा कि दोषी पाए जाने पर मौके पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि मौजूदा जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जबकि नगर निगम ने जुर्माने की रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन मौके पर जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था। इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र व अधिवक्ता रजत अनेजा ने पीठ को बताया कि मौके पर जुर्माना लगाने के प्रावधान से मच्छरों के प्रजनन पर रोक में सफलता मिलेगी।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को इन पहलुओं के बारे में विचार करने और अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। उच्च न्यायालय पिछले साल तेजी से डेंगू के मामले बढ़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 28 मई 2022

मीट मार्केट की आधी दुकानें सील

■ प्रस, नई दिल्ली : डाबड़ी मोड़ के पास जिस मीट मार्केट को नियमित करने के लिए पार्षदों ने पिछले 5 सालों से पॉलिसी बनाने की कवायदें की थी, उनका कार्यकाल खत्म होते ही एमसीडी ने मार्केट की आधी दुकानें सील कर दी हैं। मीट मार्केट के एक हिस्से में बनीं 16 दुकानें शुक्रवार को सील कर दी गईं। दूसरे हिस्से में बनी 20-22 दुकानों को सील करने के लिए डीडीए से रिपोर्ट मांगी है। एमसीडी अफसरों के अनुसार जैसे ही साउथ एमसीडी पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ, शॉप्स के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की। बाकी दुकानें सील करने के लिए एमसीडी ने डीडीए से रिपोर्ट मांगी है।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 28 मई 2022

अब बन सकेंगी और ज्यादा ऊंची मल्टीलेवल पार्किंग

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली : डीडीए ने मल्टीलेवल कार पार्किंग के नियमों को लेकर मास्टर-प्लान 2021 में एक बार फिर संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब नई मल्टीलेवल कार पार्किंग साइट्स में ऊंचाई संबंधित रोक नहीं होगी। डीडीए अधिकारियों के अनुसार, हालांकि इसके लिए संबंधित सिविक एजेंसियों की मंजूरी भी अनिवार्य होगी।

अधिकारियों के अनुसार संशोधन के अनुसार मल्टीलेवल कार पार्किंग की साइट 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के साथ होनी चाहिए। साथ ही इसकी विभिन्न एजेंसियों जैसे संबंधित सिविक एजेंसी व ट्रैफिक पुलिस से फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी होनी चाहिए। इन बदलावों को लेकर 45 दिनों के अंदर सुझाव व आपत्तियां मांगी गई थी। लेकिन इतने दिनों में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिले हैं। जिसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 28 मई 2022 ED

सीसीटीवी और गेटों से दिलशाद गार्डन ओ-पॉकेट सुरक्षित बनाने की पहल

'रात को खुला रहता है सिर्फ एक गेट, सेंधमारी-चोरी पर कंट्रोल'

Shanker.Singh
@timesgroup.com

Photos : Surender Kumar

सुरक्षा ऑडिट के दौरान सीमापुरी पुलिस और लोगों ने पॉकेट के सुरक्षा इंतजामों और समस्याओं का जायजा लिया

■ नई दिल्ली: यमुनापार के सीमापुरी थाना इलाके में आता है दिलशाद गार्डन का ओ-पॉकेट। दिलशाद कॉलोनी के करीब ये दिलशाद गार्डन का अंतिम छोर है। एनबीटी सुरक्षा कवच के तहत इस पॉकेट को सुरक्षा ऑडिट के लिए चुना गया। सीमापुरी थाना पुलिस, रेजिडेंट्स वेलफेयर असोसिएशन, मार्केट वेलफेयर असोसिएशन और सीनियर सिटिजन फोरम के साथ पॉकेट के सुरक्षा इंतजामों और समस्याओं का जायजा लिया गया। कॉलोनी में गेट लगे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक की तरफ से जल्द और कैमरे लगाने हैं।

अंकुश लगाने को बने बूथ: ओ-पॉकेट सीमापुरी विधानसभा एरिया में पड़ता है, जो निगम के दिलशाद गार्डन जोन में आता है। डीडीए के 434 जनता फ्लैट्स ताहिरपुर की तरफ हैं। आरडब्ल्यू सचिव संजय जैन ने बताया कि मंदिर वाली गली से डिस्ट्रिक्ट पार्क के बराबर वाली सड़क से सीधा करुणा हॉस्पिटल वाले रोड पर निकला जा सकता है। स्ट्रीट क्रिमिनल इसी का इस्तेमाल वारदात के लिए करते हैं। एसएचओ विनय ने कॉलोनी वालों मशविरा के बाद दोनों तरफ अब पुलिस पोस्ट बनाने का काम शुरू किया। इन्हें जल्द चालू किया जा रहा है। यहां रात को 'चार-ओ-चार' भी चलता है। पुलिस ने कई युवकों को पकड़ा भी है।

कॉलोनी में गेट और कैमरे

सिर्फ एक गेट खुला: पॉकेट में 11 गेट लगाए गए हैं, जिनमें से तीन मेन गेट हैं। कॉलोनी वालों का कहना है कि अगर तीन में से दो गेट बंद हो जाएं तो बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सकती है। लेकिन कॉलोनी के भीतर दुकानें भी हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही गेट बंद हो पाता है। दो तरफ के मेन गेट खुले रहने से चालक सवार एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से आसानी से निकल सकते हैं। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष प्रवीण कस्सन कहते हैं कि रात के समय एक ही गेट खुला रखा जाता है, जिस पर गार्ड तैनात रहता है। इसलिए सेंधमारी और चोरी की वारदात पर अंकुश लगा है।

सीसीटीवी कैमरों से लैस: दिल्ली सरकार से करीब 20 कैमरे लगाए गए हैं। इसके लिए कई कारोबारियों ने अपनी दुकान और रेजिडेंट ने अपने घरों के बाहर लगभग 15 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सभी चालू हालत में हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाती है। ताहिरपुर रोड के साथ डीडीए का डिस्ट्रिक्ट पार्क है।

स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर आवारा और अपराधी किस्म के लड़कों के जमावड़ा लगा रहता है। दिलशाद गार्डन के सभी पार्कों में ओपन एयर जिम और नए झूले लगाए गए हैं, लेकिन उनका पॉकेट इससे वंचित है। सेक्टर पार्क पुराना झूला है, जो टूट पड़ा है। गंदे पानी भी एक समस्या है।

"पॉकेट में चार पार्क हैं, जिनका रखरखाव निगम नहीं कर रहा है। इसलिए मोहल्ले के लोगों ने खुद ही पार्कों को डिवेलप करने का फैसला किया। फिलहाल एक पार्क सुंदर बना दिया गया है। – प्रवीण करनानी, अध्यक्ष आरडब्ल्यूए

"मंदिर वाली सड़क डिस्ट्रिक्ट पार्क के बगल वाली रोड से मिलती है। दोनों गेट खुले रहने से बदमाशों को खुला रास्ता मिल जाता है। हालांकि अब दोनों तरफ पुलिस पोस्ट बन रहे हैं। – संजय जैन, सचिव आरडब्ल्यूए

"करुणा हॉस्पिटल वाले रोड पर कॉलोनी से लगता हुआ पीडब्ल्यूडी का नाला है, जिसकी लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। हल्की बारिश होने पर पानी सड़क पर आ जाता है। – एसपी जैन, सलाहकार मार्केट असोसिएशन

"पानी काफी समय से गंदा आ रहा है और बदबू आती है। कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बीमारियों को खतरा बना रहता है। – ओमपाल सिंह, स्थानीय नागरिक

"ताहिरपुर रोड से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट पार्क है। इसके आसपास कुछ लोग तारों को जलाते हैं, जिससे पल्यूशन फैलता है। पार्क के भीतर कुछ नशेड़ी बैठे रहते हैं, जो वारदातें भी करते हैं। – राधा कृष्ण, सचिव सीनियर सिटिजन फोरम

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **THE INDIAN EXPRESS**, SATURDAY, MAY 28, 2022

Traffic police draw up list of 200 waterlogging hotspots in capital

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, MAY 27

AHEAD OF the monsoon season, the Delhi Traffic Police identified 211 waterlogging hotspots and has written to all civic agencies concerned — Public Works Department (PWD), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA), Irrigation and Flood Control Department — to install pumps and desilt drains on time to prevent flooding.

Of the total hotspots, 132 (mostly stormwater drains) are under the PWD as compared to 147 locations last year, showing an improvement, said officials.

"Desilting work has started in several divisions and the first phase will be completed by June 15. We have also identified 15 critical locations where underground sumps, with a capacity of nearly 7-7.5 lakh litres, and permanent pump houses, with more than 500 horsepower, are being constructed to release water immediately," said a senior PWD official.

The department is also constructing stormwater drains which will have the capacity to drain out 60 lakh litres of water per hour. Some critical locations where sumps, permanent pump houses and stormwater drains are being constructed include Pul Prahaladpur underpass, IP Estate in front of WHO building, under Zakhira flyover, Jahangirpuri Metro station, Loni Road roundabout, Azadpur market underpass among other areas.

Waterlogging is a perpetual issue in the national capital. Delhi also saw its wettest monsoon in 46 years last year — the IMD's Safdarjung observatory, which provides representative data of the city, recorded 1,136.8 mm of rainfall between June 1 and 2.30 pm on September 11, 2021.

"We have started our monsoon preparation earlier this year. Instructions have been issued to all engineers and officers concerned for immediate action," added the official. Further, all district magistrates (DMs) are holding meetings with Delhi Police and other departments concerned on the issue of waterlogging.

PWD Minister Manish Sisodia had earlier directed the department to complete desilting work by May 31 and said strict action will be taken against the officer concerned in case of laxity. However, officials said, only 40% of the work has been completed so far.

"By June 15, 100% desilting will be done," said another official.

According to officials in the Irrigation and Flood Control department, which handles 57 large drains in the city, 85% desilting work is completed and the rest will be done in next two weeks.

The PWD, which maintains around 1,400 km of key roads, is also installing 14 new pumps, repairing around 130 pumps, and is also installing hooters, alarms, and CCTV cameras to ensure live feed of water flow at critical locations.

MONSOON PREP

211 waterlogging hotspots

132 spots under PWD this year

147 under PWD last yr

JUNE 15: Target to complete Phase 1 of desilting

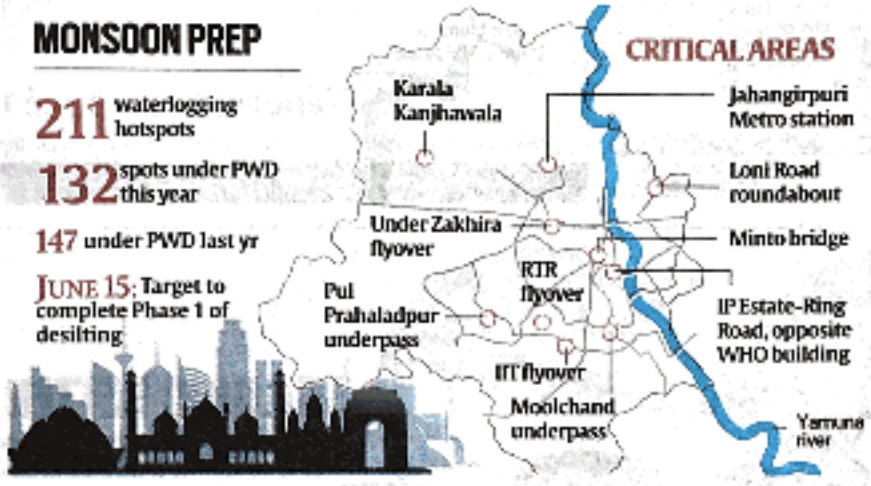

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS । संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 29 मई 2022 ATED------------------

अशोक विहार में वर्ल्ड क्लास नर्सरी बनाने का प्लान, LG ने किया दौरा

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, ग्रीन कवर बढ़ाने पर खासा जोर दे रहे दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को अशोक विहार के खोजा वाला बाग का दौरा किया। यहां 25 एकड़ का एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। एलजी का इरादा है कि यहां पर एक ऐसी विश्वस्तरीय नर्सरी बनाई जाए, जिसे इको टूरिज्म हब के रूप में डिवेलप करके उसका दोहरा फायदा उठाया जा सके। इस जगह पर कैसे हरियाली विकसित की जाए, इस संबंध में एलजी ने डीडीए के अधिकारियों से हफ्ते भर के अंदर पूरी टाइमलाइन के साथ एक ठोस प्लान तैयार करने के लिए कहा है। विजिट के दौरान एलजी के साथ एमसीडी के स्पेशल ऑफिसर, डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर समेत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के

एलजी का इरादा नर्सरी को इको टूरिज्म हब के रूप में डिवेलप करने का है

वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

एलजी का मानना है कि प्रस्तावित नर्सरी न केवल बागवानी से जुड़ी दिल्ली की तमाम जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा माध्यम बनेगी, बल्कि इसे इको टूरिज्म के लिए दिल्ली के लोगों की पसंदीदा जगह के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा। करीब 25 एकड़ में फैली यह जगह अभी बंजर हालत में है, लेकिन जब इस पर विश्वस्तरीय नर्सरी बनेगी, तो यहां कई तरह के हर्बल, मेडिसिनल और अन्य तरह के पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यहां हरियाली के साथ वॉकिंग ट्रैक्स, कैफेटेरिया और हरा-भरा लॉन बनाने, नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने और तरह-तरह के फूलों और पौधों की प्रदर्शनी लगाने की भी योजना है।

Sunday Hindustan Times NEW DELHI SUNDAY MAY 29, 2022

[IN NORTHWEST DELHI'S ASHOK VIHAR]

LG asks DDA to plan 'world-class' nursery

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Two days after taking charge, Delhi lieutenant governor (LG) Vinai Kumar Saxena on Saturday directed the Delhi Development Authority (DDA) to come up with a concrete timeline for developing a "world-class" nursery in north-west Delhi's Ashok Vihar within a week.

A statement from the LG's office said Saxena inspected the proposed 25-acre plot situated in Khoja Wala Bagh at Ashok Vihar on Saturday and directed DDA officials to ideate the nursery in such a way that it can also act as an eco-park for visitors.

A STATEMENT FROM SAXENA'S OFFICE SAID HE INSPECTED THE PROPOSED 25-ACRE PLOT IN KHOJA WALA BAGH AT ASHOK VIHAR

"The L-G issued instructions to the DDA — the agency owning the identified land — to put forth a plan of action with concrete timelines in a week's time. The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment and create a green space where different tenets of sustainable development could co-exist," said the statement.

According to the statement, the plot, which is currently fallow, once developed, will have different varieties of indigenous, medicinal, exotic, ecology and topography-compliant flora available for use by government agencies as well as citizens. It is also expected to feature landscaped greens, a cafeteria, walkways, public utilities and flower display to attract visitors.

"Being developed in the midst of the Wazirpur industrial area, this green patch will go on to serve as the much-needed oxygenating lungs of the hitherto polluted neighbourhood. Heavy footfall is expected from residents of surrounding areas, including Ashok Vihar, Wazirpur, Shalimar Bagh, Azadpur and other residential colonies," said a spokesperson from the L-G office.

Situated beside the Jailor Wala Bagh "in-situ slum rehabilitation" project under the flagship Pradhan Mantri Awas Yojna Scheme (PMAY) by the DDA, the nursery will provide an "enhanced eco-friendly environmental experience" to the "most deprived sections", the official said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 29, 2022

Committee to take a call on deletion of 230 waterbodies

Priyangi.Agarwal@timesgroup.com

New Delhi: After the Wetland Authority of Delhi received requests from land-owning agencies to delete 230 wetlands from the identified list of 1,045 waterbodies, field squads have been preparing red documents for each wetland in its current state. An expert committee will review these documents to recommend whether they need to be retained on the list, deleted, or if their revival is possible.

The land owning agencies have informed the authority that buildings, public services, unauthorised colonies, drains, agricultural land and others have come up at these places. Of the total 230 such waterbodies, 221 are under Delhi Development Authority, six under Delhi Jal Board and three are under the revenue department.

06
WATER BODIES UNDER DELHI JAL BOARD

A senior official of the authority said, "Red documents have been prepared for 194 waterbodies so far, and work is underway for the remaining waterbodies. Our target is to place red documents of these 230 wetlands before the expert committee by May 31."

C R Babu, professor emeritus and head of the Centre for Environmental Management of Degraded Ecosystems, who is heading the expert committee, said, "The requests of deletion of waterbodies from the list suggests that they are on the verge of extinction. The field squad is preparing red documents listing the present condition of wetlands, like if there is a scope of rejuvenation or they have been converted into sewage ponds or human settlement or they have been encroached upon."

As not a single waterbody in Delhi has a wetland tag under the Wetlands (Conservation and Management) Rules of 2017, at least 20 in the capital are expected to be notified this year. The wetland authority has decided to complete the process of sending a recommendation to the state government for notification by August 2022 and the final notifications by December 2022.

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 29, 2022

Eco park on the cards at Ashok Vihar, LG seeks plan in a week

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor Vinai Kumar Saxena on Saturday asked Delhi Development Authority (DDA) to explore the possibilities of developing a world class nursery-cum-ecotourism hub in north Delhi's Ashok Vihar.

The LG, accompanied by top bureaucrats, including DDA vice-chairman, MCD special officer and MCD commissioner, visited a few possible locations and ultimately zeroed down on a 25-acre land parcel in Ashok Vihar's Khoja Wala Bagh. Saxena has issued instructions to DDA, which owns the proposed plot of land, to prepare the action plan with concrete timelines within a week.

25
ACRE LAND CHOSEN FOR THE ECO PARK

This was Saxena's third field visit since he took over as the LG.

The proposed nursery, said officials, will not only serve as a common and extensive resource pool for sourcing horticultural requirements of the city but also serve as a favoured destination for ecotourism for the citizens and visitors of Delhi. "The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment of land and create a green space where different tenets of sustainable development could coexist," said an official, adding that there would be negligible use of concrete on the project.

To come upon 25 acres of fallow and wasteland, the nursery once developed will have different varieties of indigenous, medicinal, exotic, ornlogy and topography compliant flora available for use by government agencies as well as the citizens, the LG office said in a statement. It will also house landscaped greens, cafeteria, walkways, public utilities and an flower display that would serve as a re-creational destination and tourist attraction.

Situated right beside the Jailor Wala Bagh, an in situ slum rehabilitation project of DDA under the flagship Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme, the nursery will not only provide an enhanced eco-friendly environmental experience to the most deprived sections but will also serve as a go-to health and recreational destination for surrounding areas, including Ashok Vihar, Wazirpur, Shalimar Bagh, Azadpur and other residential colonies of north Delhi.

With the industrial area of Wazirpur just a stone's throw away, officials said the eco park would also help in maintaining the oxygen level of the polluted neighbourhood.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- TED------------------

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2022

स्वागतयोग्य योजना

दिल्ली में पहली विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने की उपराज्यपाल की योजना स्वागतयोग्य है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर निकलकर यहां की समस्याएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राजधानी में विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने के लिए स्थान का चयन करने के उद्देश्य से उन्होंने शनिवार को विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद बाहरी दिल्ली क्षेत्र के अशोक विहार में खोजा वाला बाग इलाके में 25 एकड़ भूमि चयनित की। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एक सप्ताह में पूरी योजना बनाकर दें।

> राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने जैसे कई कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है

देश की राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या पूरे साल रहती है। इसकी वजह से दिल्ली के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। इस समस्या के मद्देनजर यह जरूरी है कि यहां पर्यावरण को बेहतर बनाने के विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली को दुनिया का एक बेहतरीन महानगर बनाने के लिए उसके सुंदरीकरण पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में उपराज्यपाल की दिल्ली में विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने की योजना इन दोनों पहलुओं से खासी लाभदायक साबित होगी। यह नर्सरी न सिर्फ दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर लगाने के लिए बड़ी संख्या में पौधे उपलब्ध कराएगी, बल्कि पर्यावरण से जुड़े पर्यटन के मद्देनजर भी लोगों व राजधानी में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए भी यह योजना काफी लाभदायक साबित होगी। ऐसे में डीडीए को उपराज्यपाल के निर्देशों पर अमल करते हुए जल्द इस योजना को धरातल पर लाना चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ जल्द मिल सके।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2022

तीन महीने के लिए फिर खुला लैंड पूलिंग पोर्टल

- 28 मई से 28 अगस्त तक भू-अधिग्रहण के लिए पंजीकरण करा सकेंगे दिल्ली के किसान
- डीडीए के पोर्टल के जरिये भू-स्वामी ले सकते हैं अपने दस्तावेज या आवेदन संबंधी जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को लैंड पूलिंग पोर्टल को तीन महीने के लिए फिर खोल दिया। अब किसान 28 मई से 28 अगस्त तक अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन को डीडीए के पास पंजीकृत करा सकेंगे। फरवरी में पोर्टल को बंद कर दिया गया था। लैंड पूलिंग नीति में कुछ बदलाव के बाद इसे फिर खोला गया है।

केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2018 को लैंड पूलिंग नीति की अधिसूचना जारी की थी। शुरुआती दौर में कुछ गांवों की जमीन को शहरी ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा न होने के कारण इसके दायरे में नहीं रखा गया था। लेकिन, बाद में कुल 109 सेक्टरों में विभाजित कर इस योजना को छह जोन में बांट दिया गया। योजना के तहत दिल्ली में 17 लाख आवास बनाए जाने हैं।

जोन पी टू में सेक्टर दो व तीन, जोन एन में सेक्टर 10 और जोन एल में सेक्टर तीन में जल्द किसानों के सशर्त समूह बनाए जाएंगे। इसके बाद निवेशकों-बिल्डरों के साथ बैठक होगी। फिर 60 और 40 के फार्मूले पर सेक्टरों को विकसित किया जाएगा। डीडीए ने विशेष पोर्टल भी बनाया है जिसके जरिये भू-स्वामी अपने दस्तावेज या आवेदन संबंधी जानकारी ले सकते हैं। योजना में जोन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-2 में आने वाले 104 गांव शामिल हैं। यह पूरा क्षेत्र 129 सेक्टरों में विभाजित है। यदि भू-स्वामी कंसोर्टियम बनाने में विफल रहते या उस विशेष सेक्टर में 70 प्रतिशत शामिल पूल्ड भूमि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में नोटिस रद हो जाएगा। लैंड पूलिंग क्षेत्र में सभी सेक्टरों के लिए भू-स्वामियों के नक्शे के विवरण डीडीए की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट जीओवी डाट इन/रेफरेंस-मैप्स पर उपलब्ध हैं। सेक्टर-जोन में 210 हेक्टेयर विकास योग्य भूमि शामिल है, जिसमें से 156 हेक्टेयर भूमि वाले भू-स्वामी विकास के लिए आगे आए हैं। इसमें भी पूल की गई भूमि शामिल नहीं है।

पिछली बार 10 दिसंबर, 2021 को पालिसी के लिए पंजीकरण खोला गया था, जो 28 फरवरी, 2022 को समाप्त हुआ। 10 दिसंबर तक डीडीए को मिली 7275.45 हेक्टेयर जमीन में 28 फरवरी तक 344.05 हेक्टेयर जमीन का और इजाफा हुआ है। यानी, अब 7619.95 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हो चुकी है।

डीडीए की खाली जमीन पर बनेगी विश्वस्तरीय नर्सरी

- अशोक विहार में 25 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, उपराज्यपाल ने शनिवार को किया साइट का दौरा
- ईको-टूरिज्म का बनाया जाएगा बड़ा केंद्र, एक सप्ताह में रूपरेखा तैयार करने का दिया गया है निर्देश
- सरकारी विभागों के साथ ही नागरिकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे यहां तैयार होने वाले दुर्लभ पौधे

<< अशोक विहार में डीडीए की खाली जमीन पर नर्सरी बनाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा करते उपराज्यपाल • सौ. राजनिवास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 25 एकड़ खाली जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी तैयार की जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को खोजा वाला बाग अशोक विहार में स्थित इस जमीन का निरीक्षण किया। यहां बनने वाली नर्सरी में न सिर्फ देशी-विदेशी पौधों को तैयार किया जाएगा, बल्कि इसे राजधानी में इको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र भी बनाया जाएगा।

उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने के साथ ही लगातार राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे विनय कुमार सक्सेना शनिवार को अशोक विहार पहुंचे। उन्होंने यहां डीडीए की जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी और ईको-टूरिज्म हब बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह में डीडीए को इस पूरी योजना की रूपरेखा तैयार करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान एमसीडी के विशेष अधिकारी, डीडीए उपाध्यक्ष, निगम आयुक्त व अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।

विदेशी व दुर्लभ किस्म के पौधे भी होंगे तैयार: नर्सरी में स्थानीय प्रजाति के साथ-साथ विदेशी और दुर्लभ किस्म के पौधे भी तैयार होंगे, जिन्हें सरकारी विभागों के साथ-साथ नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। कैफेटेरिया और पैदल पथ बनेंगे। पर्यटन के लिहाज से भी इसे एक आकर्षक जगह के तौर पर तैयार किया जाएगा। यह जगह वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसलिए इस पूरी जगह को हरा-भरा बनाने से लोगों को ज्यादा आक्सीजन भी मिलेगी। इससे लोगों को कुछ हद तक प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा।

स्वागतयोग्य योजना » संपादकीय

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान ——— DATED नई दिल्ली, रविवार, 29 मई 2022

एयरपोर्ट जाने वाली सभी सड़कों की स्थिति सुधारें : उपराज्यपाल

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अपना पदभार संभालते ही सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खासकर एयरपोर्ट को बाकी दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कों को लेकर एलजी ने विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं।

एयरपोर्ट की ओर आने-जाने वाली सड़कों पर जाम और गंदगी पूरी तरह से खत्म की जा रही है। इसी कड़ी में बीते तीन दिन से दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी जोन के सफाई कर्मचारी-अधिकारी से लेकर निगम उपायुक्त तक एयरपोर्ट आने-जाने वाली सड़कों पर अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था को लेकर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के चालान भी काटे गए हैं।

पीडब्ल्यूडी-एनएचएआई का पांच लाख का चालान कटा: उपराज्यपाल के दौरे के बाद दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि तीन दिन के अंदर इस जुर्माने की राशि को जमा करवाएं। बता दें कि उपराज्यपाल ने दौरे के दौरान धौला कुआं क्षेत्र में गंदगी पाई थी।

दो सड़कों पर चल रहा है अभियान : दिल्ली नगर निगम ने तीन दिन से धौला कुआं से गुड़गांव जाने वाले और द्वारका से नजफगढ़ जाने वाले रूट पर अभियान चला रहा है। इस दौरान दिल्ली कैंट इलाके में निगम की ओर से अवैध रूप से लगी रेहड़ी-पटरी को भी हटाया गया है। यह दोनों सड़कें एयरपोर्ट से दिल्ली की ओर आने-जाने के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती हैं।

अशोक विहार में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते एलजी वीके सक्सेना। • हिन्दुस्तान

डीडीए की खाली भूमि पर नर्सरी बनेगी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण की 25 एकड़ खाली जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी तैयार की जाएगी। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को खोजा वाला बाग अशोक विहार में स्थित जमीन का निरीक्षण किया। यहां बनने वाली नर्सरी में न सिर्फ देसी-विदेशी पौधों को तैयार किया जाएगा, बल्कि इसे राजधानी में ईको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र भी बनाया जाएगा।

उप राज्यपाल ने अशोक विहार क्षेत्र में खाली जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां नर्सरी और ईको टूरिज्म हब तैयार करने के निर्देश दिए। एक सप्ताह में योजना की रूपरेखा तैयार करने को कहा।

25 एकड़ भूमि पर अशोक विहार में बनाई जाएगी

कैफेटेरिया और पैदल पथ भी बनेगा: नर्सरी में स्थानीय प्रजाति के साथ-साथ विदेशी और दुर्लभ किस्म के पौधे भी तैयार किए जाएंगे। नर्सरी के लिए चुनी गई यह जगह वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसलिए इस पूरी जगह को हरा-भरा बनाने से लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन भी मिल सकेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग पोर्टल को तीन महीने के लिए फिर से खोला

सुविधा : किसानों को पोर्टल पर भूमि पंजीकृत कराने का एक और मौका

अच्छी खबर

■ राजनाथ चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को लैंड पूलिंग पोर्टल को तीन महीने के लिए फिर से खोल दिया है। लोग 28 अगस्त तक अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन को डीडीए के पास पंजीकृत करा सकते हैं। इससे पहले, फरवरी में पोर्टल को बंद कर दिया गया था। लैंड पूलिंग नीति में कुछ बदलाव के बाद इसे फिर खोला गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी अब किसानों से मुलाकात कर उन्हें भूमि का पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करेंगे।

केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2018 को लैंड पूलिंग नीति की अधिसूचना जारी की थी। शुरुआती दौर में कुछ गांवों की जमीन को शहरी ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा न होने के कारण इसके दायरे में नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में कुल 109 सेक्टरों में विभाजित कर इस पॉलिसी को छह जोन में बांट दिया गया। योजना के तहत दिल्ली में 17 लाख आवास बनाए जाने हैं।

17 लाख आवास राजधानी में बनाए जाएंगे योजना के तहत

28 अगस्त तक अपनी जमीन पंजीकृत करा सकेंगे दिल्ली के किसान

7619.95 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर

अंतिम बार 10 दिसंबर 2021 को पॉलिसी के लिए पंजीकरण खोला गया था, जो 28 फरवरी 2022 को ही समाप्त हुआ है। 10 दिसंबर तक डीडीए को मिली 7275.45 हेक्टेयर जमीन में 28 फरवरी तक 344.05 हेक्टेयर जमीन का और इजाफा हुआ है। अब 7619.95 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हो चुकी है।

28 फरवरी तक 290 आवेदन आए

डीडीए के अनुसार, 10 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच कुल 290 आवेदन और 344 हेक्टेयर जमीन हासिल हुई है। इसमें जोन जे और पी-1 में भी आवेदन मिले हैं और जमीन भी पंजीकृत हुई है।

> 2019 में डीडीए को जमीन दे दी थी, लेकिन आज तक जमीन पर कुछ नहीं हो पाया है। जमीन पर अभी तक खेती ही हो रही है। डीडीए आज तक योजना को सिरे नहीं चढ़ा पाया है।
> –रामबीर शौकीन, किसान

> डीडीए ने न तो जमीन ली है, न जमीन हमारे पास है। अभी तक खेती-किसानी हो रही है। कभी-कभी डीडीए के अधिकारी जमीन पर दौरा करने आते हैं, लेकिन आज तक विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है। –सुनील डबास, किसान

विकासकों-किसानों के साथ बैठक होगी। अधिकारी ने बताया कि जोन पी 2 में सेक्टर दो व तीन, जोन एन में सेक्टर 10, जोन एल में सेक्टर तीन में जल्द किसानों के सहायता समूह बनाए जाएंगे। इसके बाद विकासकों-किसानों के साथ बैठक होगी। फिर 60 और 40 के फार्मूले पर सेक्टरों को विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा। डीडीए ने विशेष पोर्टल भी बनाया है, जिससे भू-स्वामी दस्तावेज अथवा आवेदन संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। योजना में जोन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-2 में आने वाले 104 गांव शामिल हैं।

पूरा क्षेत्र 129 सेक्टर में विभाजित : अधिकारी ने कहा, यह पूरा क्षेत्र 129 सेक्टरों में विभाजित है। भू-स्वामी कंसोर्टियम बनाने में विफल रहते हैं या विशेष सेक्टर में 70 प्रतिशत न्यूनतम पूल्ड भूमि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे नोटिस रद्द हो जाएगा। लैंड पूलिंग क्षेत्र में भू-स्वामियों नक्शे के विवरण डीडीए की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट डीडीए डॉट जीओवी डॉट इन/ ऐप्लेस-मैप्स पर देखे जा सकते हैं। सेक्टर तीन में लगभग 210 हेक्टेयर विकास योग्य भूमि शामिल है, जिसमें से 156 हेक्टेयर भूमि वाले भू-स्वामी विकास के लिए आगे आए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE SUNDAY EXPRESS, MAY 29, 2022

Experts divided on lakhs of trees along floodplains

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, MAY 28

FIERCELY GUARDED from grazing cattle on the Yamuna's floodplains in Northeast Delhi's Garhi Mandu are lakhs of saplings and trees planted there in lieu of those felled for infrastructure projects. Sections of the floodplain near the Signature Bridge are visibly green, even from a distance.

Such dense plantations on the active floodplains are not desirable, said A K Gosain, professor emeritus at IIT-Delhi, who is a member of the expert committee constituted on orders of the NGT to monitor rejuvenation of the river and its floodplains. "This is the active floodplain, which means it gets inundated every year. Anything that you put here is a resistance to the flow. Plantations should be as far from the floodplain as possible," he said.

Repeated flooding also means it is difficult to protect saplings. Several hectares of the floodplains where saplings have been planted is low-lying land that is flooded in the monsoon. The last time the area witnessed major flooding was in 2019, said a forest department staffer in charge of the plantation sites at Garhi Mandu. If the water recedes quickly, there is no damage to trees, he said. But in some parts of the floodplains, like a patch at Shastri Park, saplings were destroyed by water that remained stagnant for a long while. Around 16,000 saplings will be planted in the area this year, said Aditya Madanpotra, Deputy Conservator of Forests, Central Division, adding that suitable species like sheesham, that can withstand flooding, would be planted.

Compensatory plantation on the floodplains in Northeast Delhi's Garhi Mandu. Express

To illustrate, large swathes of a 19-hectare patch used for compensatory afforestation of an NHAI project are densely covered in trees planted in the 2019-20 financial year. But small patches were incongruously empty — the saplings have been planted, but have not quite made it. "The trees that survived are on higher land," the forest department official said.

In the Central Forest Division, within which much of the floodplain falls, compensatory plantation has been carried out on 245 hectares, with 2,97,789 saplings, as per records.

Additionally, around 357.6 hectares was handed over by DDA to the Forest department for plantation activity from 1975 onwards. Around 1,63,000 saplings were planted here. At Garhi Mandu, a total of 42.1 acres of land is now a 'city forest', where there's a mud track for walks.

In January, at a meeting of the expert committee, Gosain noted, as per the minutes: "Delhi government should be directed that such compensatory activities should be prevented in the floodplain and if required, be only carried out in the outermost area of the floodplain, where floodwater reaches only in 1 in 50 year or so."

However, Shashank Shekhar, professor, Department of Geology, Delhi University, said, "If it's a native species which is suitable for the river banks, then it's good." The plantations must be done in a scientific manner, with the correct species, and must not be monoculture plantations, he added.

Faiyaz Khudsar, scientist in-charge of the Biodiversity Parks Programme and the Yamuna Biodiversity Park, identified species that are suitable for the floodplains — trees like kadamb, sheesham, arjun, semal and jamun for the top storey, and others like amla, bael and doodhi for the middle storey. While the forest department has planted some of these species, it has also used some that are not usually found in such areas. Neem, pilkhan and jungle jalebi, for instance, are not suitable species for the floodplains, Khudsar said.

At a plantation site near the Shastri Park Metro station, out of 3,244 trees planted, 850 were jungle jalebi, 560 were pilkhan trees and more than 180 were neem trees.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times DATED– NEW DELHI MONDAY MAY 30, 2022

City to get 20 'mini forests' as part of green plan; focus on East Delhi's congested spots

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Municipal Corporation of Delhi plans to develop at least 20 mini forests in densely populated areas, especially in the heavily concretized Yamuna region, as part of its annual greening action plan for 20222. The horticulture wing of the civic body will plant saplings of 85,000 trees and 520,000 shrubs this year, showed data released by the corporation on Sunday.

A senior municipal official from the horticulture department said due to shortage of space, existing parks, regional offices, schools, dispensaries, roadsides, community centres have been identified for the plantation drive. "In east Delhi, we had carried out Miyawaki plantation near Mayur Vihar around a year ago. We are satisfied with the progress. Five more such Miyawaki mini-forests will be developed in east Delhi," said the official.

"This year, mini forests with high density plantation will be developed at 20 locations. Maximum number of high-density plantation hotspots will be developed in Keshavpuram zone, where seven sites have been selected for the project," said the senior official.

In terms of distribution of the 85,000 new trees, the two zones in east Delhi (Shahadra north and Shahadra south) will get saplings of 20,000 trees.

Japanese roots in Delhi

WHAT'S A MIYAWAKI FOREST?
Pioneered by the Japanese Botanist Akira Miyawaki, the forests have thousands of native tree species grown closely together in a small patch of area in a manner that the greens receive sunlight only from the top and they grow upwards, instead of sideways. In comparison to a conventional forest, a Miyawaki forest is not only several times denser, but it can also be ready in two to three years.

Space crunch in east Delhi

The two zones under East Delhi have the highest proportion of unplanned areas (over 80%) with relatively fewer parks and green belts, posing a serious challenge to the target of increasing green cover in the area. Out of more than 15,000 parks under MCD, around 15% parks are located in east Delhi.

The civic body will plant saplings of 20,000 trees and 80,000 shrubs in the region. A senior horticulture official from east Delhi said that the corporation will focus on filling the gap between existing trees, replacement of dead trees and increasing the green cover in 92 parks, which have been handed over to the EDMC by the Delhi Development Authority (DDA) last year.

"In comparison to other parts of the city, the space available in east Delhi is minimum as most of the colonies have come up in an unplanned manner. We can only plant new trees along foot paths, central verges and gaps between boundary walls of parks. No new major road stretches have come up in east Delhi so Miyawaki forest technique is ideal in terms of developing dense mini-forests in existing spaces," said the official.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MAY 30, 2022

MCD to go beyond parks to plant 85k saplings

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: With a target to plant nearly 85,000 saplings and 5.2 lakh shrubs this year, Municipal Corporation of Delhi (MCD) has decided to utilise its open spaces at dispensaries, community halls, schools, zonal offices, colonies, roads, etc for the purpose, in addition to public parks.

Officials said a majority of the parks did not have enough spaces to accommodate more saplings and, therefore, they had identified new sites. However, the civic body had singled out some parks/barren land in the middle of congested areas, wherein dense plantation would be done to develop mini-forests.

The erstwhile east corporation had identified three sites for dense plantation using Miyawaki technique this year.

"We have submitted a target to plant 20,000 saplings in Shahdara north and south zones to the Delhi government forest department. The remaining 80,000 would be shrubs. We have already prepared 25,000 saplings (more than the requirement) of indigenous breeds at our nurseries and about 65,000 shrubs. Their plantation will start with the beginning of monsoon. The rest of the shrubs will be procured soon," said RK Singh, horticulture director (II).

In both the zones, three mini-forests were developed till the last financial year, including at Mayur Vihar, GD Colony and Ghazipur. In this financial year, there are plans to develop five more at Nandnagri, Sunder Nagri, Yamuna Vihar and Welcome.

"These sites are being developed by an NGO without any investment from the corporation. They are using the (Miyawaki) technology which helps in faster growth of plants. At GT Colony, the saplings have crossed the height of eight feet and soon these will turn into dense areas," said the official.

Plans are also afoot to develop 15 open sites/parks into mini-forests spread over 31 acres in three zones under the erstwhile north corporation. In phase-I, it had developed 18 large parks into mini-forests spread over 31.6 acres.

"We planted about 8,000 additional saplings at 18 places last year. An almost similar number will be planted at the new sites also. However, we are not going for the Miyawaki technique and are stressing upon keeping a distance between two plants so that the roots and canopy can grow properly. To avoid wild growth, grass and related plants will be grown," said Ashish Pridarshi, horticulture director (III), MCD.

The mini-forests have proper boundaries and gates with no benches to dissuade walkers from sitting unnecessarily. "Plants of indigenous varieties like neem, pilkhan, pipal, jamun, fig (ficus carica), etc are being planted because their survival rate is high," said the official.

The corporation is making arrangements to ensure sufficient water supply in these parks for the first three years and simultaneously trying to pool in NGOs for their annual maintenance.

To check the survival rates of saplings planted in the past five years, the corporations had got a third party audit done. South and east corporations had engaged India Agriculture Research Institute, Pusa Road, to conduct the audit. North corporation got the audit done by Forest Research Institute, Dehradun, in which around 75% of the saplings were found to have survived at 6,102 parks.

EXPANDING GREEN COVER

THE TARGET
To plant 85,000 trees
5.2 lakh shrubs and ornamental plants

BY WHEN
2022-23

iStock

HIGHLIGHTS

- Plants of indigenous varieties like neem, pilkhan, pipal, jamun, fig, etc, being planted because of high survival rate
- Recently transferred sites/parks from DDA to be used too
- With space in parks exhausted, dispensaries, regional offices, community halls, schools, etc, to be used for plantation
- In Shahdara south and north zone, 92 parks were transferred from DDA last year
- MCD developed 21 'mini-forests' till last year
- 20 more mini-forests to be developed this year

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- हिन्दुस्तान ----------DATED- नई दिल्ली सोमवार 30 मई 2022

डीडीए ने मास्टर प्लान में संशोधन किया, एफएआर भी बढ़ाया

फ्लैट की संख्या के बराबर पार्किंग स्थान रखना जरूरी

बदलाव

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। कार पार्किंग की परेशानी दूर करने के लिए पार्किंग बनाने के नियमों में डीडीए की ओर से बदलाव किया गया है। इसके तहत एफएआर बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। वहीं, ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में जितने आवासीय फ्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखना अनिवार्य होगा।

यह बदलाव दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के जरिए किया गया है। डीडीए की ओर से किए गए संशोधन के तहत पार्किंग स्थल के लिए वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊंचाई पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। साथ ही बहुमंजिला कार पार्किंग बनाने के लिए सड़कों की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर तय की गई है। अब तक नौ मीटर तक की सड़कों पर भी मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाई जा रही थी।

ये नए मापदंड होंगे : संशोधित प्रावधान में बहुस्तरीय कार पार्किंग प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी जैसे यातायात पुलिस व अन्य निकायों के अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। वहीं, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्गमीटर होना चाहिए। एक हजार से तीन हजार वर्गमीटर के आकार के भूखंड पर 100 एफएआर (फ्लोर एरिया अनुपात) को अनुमति होगी। तीन से 10 हजार वर्गमीटर तक के भूखंड पर एफएआर 60 होगा। 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की शेष भूमि पर एफएआर 50 होगा।

क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा

अभी प्लॉट का कुछ फीसदी हिस्सा पार्किंग स्थल के रूप में खाली छोड़ा जाता है। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आवासों की संख्या न देखकर, प्लॉट के आकार के अनुरूप पार्किंग स्थल तय किए जाते हैं। लेकिन, नए नियमों के तहत जितने आवासीय फ्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखना अनिवार्य होगा। पार्किंग के लिए स्थान तय करते वक्त आवासीय इकाइयों के क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु

- आवासीय परिसर में वाहन पार्क करने की सुविधा मिलेगी
- गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान तय हो सकेगा
- सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या कम होगी

ये बदलाव होंगे

- एफएआर टी सीमा में बदलाव किया गया है
- नए बनने वाले पार्किंग स्थलों की क्षमता बढ़ सकेगी
- 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर मल्टीलेवल पार्किंग नहीं

मौजूदा समय में यह स्थिति है

दिल्ली में मौजूदा समय में लगभग सवा करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। वाहनों की संख्या के हिसाब से दिल्ली में महज एक प्रतिशत वाहनों के लिए पार्किंग क्षमता मौजूद है।

- 62 हजार के करीब वाहन पार्किंग क्षमता है निगम की
- 18 हजार वाहनों की क्षमता है दिल्ली मेट्रो पार्किंग की
- 20 हजार वाहनों के पार्किंग की क्षमता अन्य विभागों की है

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
SATURDAY, MAY 28, 2022

DDA amends MPD-2021 for new car parking projects

New norms will reduce congestion, says official

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Agencies responsible for the maintenance of multilevel car parking (MLCP) projects are required to take measures to discourage on-street parking around the MLCPs, according to a recent amendment to the Master Plan for Delhi-2021 (MPD-2021).

According to the amendment introduced by the Delhi Development Authority (DDA), agencies operating MLCPs are responsible for the on-street parking of at least 500 metres around their buildings.

"Suitable measures have to be taken by the management agency to discourage on-street parking around the MLCPs by means of increased parking charges (at least 3 times that of MLCP) and other measures," read the amendment, which was part of a notification issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, with effect from May 12.

"The amendments were brought in for more clarity over the commercial component in new MLCPs, but some of these norms are also aimed at reducing congestion," a senior DDA official said.

The new norms have lifted the limit on the car parking building's height and the number of basements. "The height shall not be restricted, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies," the amendment read. The norms also lay guidelines on the permissible floor area ratio (FAR) – ratio of the building's total floor area to the size of the land upon which it is built – for the car parking spaces.

For plots measuring up to 3,000 square metres, the agency developing the facility can avail of a permissible FAR of 100. However, for plots above 3,000 square metres, an FAR of 100 is allowed for the first 3,000 square metres, followed by an additional FAR of 60 on the remaining land.

Previously, the FAR was capped at 100, however, the minimum plot size required is still 1,000 square metres.

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | MAY 28, 2022

NDMC gets new Chairman

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Bhupinder Singh Bhalla, a 1990 batch IAS officer has been appointed as the new Chairperson of the New Delhi Municipal Council (NDMC). He succeeds Dharmendra, a 1989-batch officer, as the civic body Chairman. Bhalla, is currently Additional Chief Secretary of Delhi.

The Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday issued an order to this effect. According to order issued by MHA, it is decided to appoint Bhupinder Singh Bhalla, IAS (AGMUT:1990), as Chairperson, New Delhi Municipal Council (NDMC) with effect from 27.05.2022.

"The notification (Hindi and English) issued in this regard is enclosed for its publication in Delhi Gazette, Extraordinary. It is further requested that Dharmendra, IAS (AGMUT:1989) may be relieved with effect from 27.05.2022. Further, Bhupinder Singh Bhalla may be directed to take over charge of post of Chairperson, N D M C Immediately," the order further stated.

Bhalla succeeds Dharmendra, , a 1989-batch officer, as civic body chairman, who has worked over ten years in Urban Sector in Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India and DDA.

millenniumpost
NEW DELHI | SATURDAY, 28 MAY, 2022

Change in MPD-2021 norms to regulate commercial dev at new parking sites

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority has brought an amendment in the Master Plan for Delhi 2021 (MPD-2021) to regulate commercial development at new multi-level car parking sites besides the height restriction has been done away with subject to clearance from statutory bodies, officials said on Friday.

Modified provisions also mandate that "MLCP (multi-level car parking) plots shall be located on roads with RoW (right of way) of 12 m and above, subject to feasibility report from a competent agency and NOC from traffic police and other statutory bodies," as per a gazette notification issued by the Union government recently.

"Whereas, certain modifications which the central government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2022(E) dated 25.05.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice," it said.

"Whereas, no objections/suggestions have been received with regard to the proposed modifications," the statement said.

Therefore, the government has made some modifications in the MPD-2021 with effect from the date (May 12) of publication of the gazette notification, it added.

"In order to compensate the cost of multi-level parking and also to fulfill the growing need of parking spaces within urban area, a maximum of 25 per cent of gross floor area may be utilised as commercial or office space," as per the earlier norm, mentioned in the notification.

According to the new norms, while the minimum plot size has to be of 1,000 sqm, 100 FAR (floor area ratio) would be allowed on plots of the size of 3,000 sqm. On plot sizes above 3,000 sqm, FAR provided for the balance land would be 60, up to 10,000 sqm. Any balance land above 10,000 sqm in a plot will have 50 FAR.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

28 मई • 2022 राष्ट्रीय सहारा ------------------------------------DATED--------------------

बहुस्तरीय पार्किंग के लिए डीडीए ने किया मास्टर प्लान-2021 में संशोधन

नई दिल्ली । राजधानी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन कर दिया है। डीडीए की संशोधित नीति के मुताबिक अब सभी बहुस्तरीय पार्किंग के प्लाट 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही होंगे। हालांकि इसके बावजूद सक्षम एजेंसी, स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने की जरूरत पड़ेगी। अब बहुस्तरीय पार्किंग के लिए कम से कम एक हजार वर्गमीटर का प्लॉट होने अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के नए मापदंडों के मुताबिक बहुस्तरीय पार्किंग के प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल एक हजार वर्गमीटर हो। इसके साथ ही 3 हजार वर्गमीटर के प्लॉट पर 100 एफएआर की अनुमति होगी। तीन हजार 10 हजार वर्गमीटर के प्लॉट के लिए एफएआर 60 मिलेगा। 10 हजार वर्गमीटर के क्षेत्रफल से अधिक वाले प्लॉट के लिए 50 एफएआर निर्धारित किया गया है। खासबात यह है कि डीडीए ने ऊंचाई पर लगी रोक हटा दी है।

फैसले का स्वागत

नई दिल्ली । भाजपा के सिख नेता सरदार मनजिन्दर सिंह सिरसा ने 1991 में पीलीभीत में 11 बेगुनाह सिखों का कत्ल करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के 34 कर्मचारियों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जमानतें रद्द करने के फ़ैसले का स्वागत किया है । यहां जारी एक बयान में सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अदालत का जमानतें रद्द करने का फैसला सारे देश में एक संदेश है कि बेरहमी के साथ किए गुनाहों के मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

अमर उजाला

नए पार्किंग स्थलों के वाणिज्यिक विकास के लिए मास्टर प्लान में संशोधन

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर वाणिज्यिक विकास को विनियमित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) में संशोधन किया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल के लिए वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊंचाई पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया गया है। संशोधित प्रावधान में बहुस्तरीय कार पार्किंग प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिए सक्षम एजेंसी की व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात पुलिस व अन्य वैधानिक निकायों के अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।

नए मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्ग मीटर होना चाहिए। 3,000 वर्ग मीटर के आकार के भूखंड पर 100 फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) की अनुमति होगी, जबकि 3,000 से 10 हजार वर्ग मीटर तक के भूखंड पर एफएआर 60 होगा और 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की शेष भूमि पर एफएआर 50 होगा। बहुस्तरीय पार्किंग की लागत की भरपाई करने के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत वाणिज्यिक या कार्यालय स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ब्यूरो

पंजाब केसरी

नए पार्किंग स्थलों के वाणिज्यिक विकास को लेकर संशोधन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर वाणिज्यिक विकास को विनियमित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) में संशोधन किया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल के लिए वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊंचाई पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया गया है। संशोधित प्रावधान में एमएलसीपी (बहुस्तरीय कार पार्किंग) प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिए सक्षम एजेंसी की व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात पुलिस व अन्य वैधानिक निकायों के अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। नए मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्गमीटर होना चाहिए, 3,000 वर्गमीटर के आकार के भूखंड पर 100 एफएआर (फ्लोर एरिया अनुपात) की अनुमति होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ अमर उजाला -------DATED 29-05-2022

खोजा वाला पार्क की 25 एकड़ भूमि पर विकसित होगी नर्सरी

उपराज्यपाल ने डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों को दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

निरीक्षण के साथ अधिकारियों से बातचीत करते उपराज्यपाल। अमर उजाला

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना लगातार तीसरे दिन भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का निरीक्षण किया। दिल्ली को अपनी पहली विश्व स्तरीय नर्सरी प्रदान करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने अशोक विहार स्थित खोजा वाला पार्क की 25 एकड़ भूखंड पर नर्सरी के लिए डीडीए को एक सप्ताह के भीतर योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

प्रस्तावित नर्सरी न केवल दिल्ली की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य और व्यापक संसाधन के रूप में काम करेगी, बल्कि दिल्ली के नागरिकों और आगंतुकों के लिए पर्यावरण पर्यटन के लिए एक पसंदीदा स्थल भी बनेगी। करीब 25 एकड़ में फैली बंजर भूमि के विकसित होने पर नर्सरी में सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध स्वदेशी, औषधीय, विदेशी, पारिस्थितिकी और स्थलाकृति के अनुरूप वनस्पतियों की विभिन्न किस्में होंगी। इसमें हरे-भरे हरियाली क्षेत्र, कैफेटेरिया, पैदल मार्ग, सार्वजनिक उपयोगिताओं और तरह-तरह के फूल भी होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डीडीए की जेलर वाला बाग इन-सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के ठीक बगल में स्थित नर्सरी न केवल सबसे वंचित वर्गों को एक बेहतर पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि अशोक विहार, वजीरपुर समेत आवासीय कॉलोनियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन स्थल की नई सुविधा भी प्रदान करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 29 MAY, 2022

L-G SAXENA INSPECTS SITE

25-acre nursery planned in Delhi

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Saturday inspected a 25-acre horticultural plot in the city where a "world-class" nursery and eco-tourism hub is planned be set up, officials said.

Saxena instructed the Delhi Development Authority (DDA) to put forth a plan of action for it with concrete timelines within a week, the Raj Niwas said in a statement.

"With the objective of providing the national capital with its first world-class nursery that would also twin as an eco-tourism hub, Lieutenant Governor V K Saxena today (Saturday) went on a site inspection of various locations across the national capital," it said.

The proposed nursery will not only serve as a common and extensive resource pool for sourcing horticultural requirements of the city but also as a favoured destination for eco-tourism for residents and visitors, the officials said.

Having zeroed in on a 25-acre plot of land in Khoja Wala Bagh Ashok Vihar, Saxena, who had earlier described himself as "Delhi's local guardian", issued instructions to the land owning agency to put forth a plan of action within a week's time, the statement said.

The lieutenant governor (L-G) was accompanied by the special officer and the commissioner of the MCD, vice-chairman of the DDA, and other senior officers of departments concerned.

"The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment of land and create a green space where different tenets of sustainable development could co-exist," the Raj Niwas statement said.

Spread over existing fallow and wasteland, the nursery once developed will have different varieties of indigenous ecology and topography-compliant medicinal and exotic flora available for use by government agencies as well as citizens, it said.

It will also house landscaped greens, cafeteria, walkways, public utilities and an inherent flower display that would serve as a recreational destination and tourist attraction for people of the city and visitors, the statement added.

Situated right beside the Jailor Wala Bagh 'in-situ slum rehabilitation' project of the DDA under the flagship Pradhan Mantri Awas Yojna Scheme, the nursery will not only provide an enhanced eco-friendly environmental experience to the most deprived sections, but will also serve as a go-to health and recreational destination for surrounding areas, the officials said.

Being developed in the heart of the Wazirpur industrial area, this green patch will go on to serve as the "much-needed oxygenating lungs of the hitherto polluted neighbourhood", the statement said.

29 मई • 2022 | सहारा

दिल्ली में 25 एकड़ क्षेत्र में नर्सरी बनाने की योजना

नई दिल्ली (भाषा) उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शनिवार को महानगर में 25-एकड़ में फैले एक बागवानी प्लॉट का निरीक्षण किया, जहां "विश्व स्तरीय" नर्सरी और पारिस्थितिकी-पर्यटन हब बनाने की योजना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

राज निवास ने एक बयान में कहा कि सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक सप्ताह के भीतर ठोस समयसीमा के साथ इसके लिए एक कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी को अपनी पहली विश्व स्तरीय नर्सरी देने के उद्देश्य से उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आज शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। यह नर्सरी पारिस्थितिकी-पर्यटन हब भी होगी।

■ उपराज्यपाल ने किया स्थल का निरीक्षण

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्तावित नर्सरी न केवल दिल्ली की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साझा और व्यापक संसाधन पूल के तौर पर काम करेगी बल्कि निवासियों और पर्यटकों के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन का पसंदीदा स्थल भी होगी। खोजा वाला बाग, अशोक विहार में 25 एकड़ की जमीन का निरीक्षण करते हुए सक्सेना ने डीडीए को एक हफ्ते के भीतर कार्य योजना पेश करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल एमसीडी के विशेष अधिकारी और आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गए थे। राज निवास ने एक बयान में कहा, 'इसका मकसद इस्तेमाल न होने वाली जमीन का क्षरण होने से बचाना, जमीन पर अतिक्रमण को रोकना और ऐसा हरित क्षेत्र बनाना है, जहां सतत विकास के विभिन्न सिद्धांत एक साथ रह सकें।' बयान के अनुसार, इस नर्सरी में हरियाली, कैफेटेरिया, सैर करने के रास्ते, सार्वजनिक सुविधाएं होंगी जो शहर के लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

THE HINDU
SUNDAY, MAY 29, 2022

L-G proposes 25-acre 'world-class' nursery

It will be developed as eco-tourism hub

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Saturday ordered the Delhi Development Authority (DDA) to come up with a concrete timeline for developing a "world-class" nursery in north-west Delhi.

According to a press release from Raj Niwas, a 25-acre plot situated in Khoja Wala Bagh at Ashok Vihar was identified for the purpose during a site inspection drive by the L-G.

Apart from serving as an extensive resource pool for sourcing horticultural requirements of the city, the nursery will also be a favoured destination for eco-tourism, Raj Niwas said.

"The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment of land and create a green space where different tenets of sustainable development could co-exist," a senior Raj Niwas official said.

Spread over 25 acres of existing fallow and wasteland, the proposed nursery, once developed, will have different varieties of indigenous, medicinal, exotic, ecology and topography-compliant flora available for use by government agencies as well as citizens.

To attract more visitors, several features such as landscaped greens, a cafeteria, walkways, public utilities and an inherent flower display have been proposed for the facility.

"Being developed in the midst of the Wazirpur industrial area, this green patch will go on to serve as the much-needed oxygenating lungs of the hitherto polluted neighbourhood," the official said, adding that a heavy footfall is expected from residents of nearby areas.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA दैनिक भास्कर नई दिल्ली, रविवार 29 मई, 2022 ' 02 DATED

एलजी ने डीडीए को दिए आदेश खोजावाला बाग में 25 एकड़ में एक सप्ताह में नर्सरी बनाएं, सड़क किनारे हरा-भरा हो

बागवानी के साथ लोगों के लिए बनेगा ऑक्सीजन 'हब'

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

आने वाले कुछ माह में ही अब दिल्ली में सड़कों पर गंदगी, बदरंग जंग खाती लोहे की ग्रिलें दिखने के जगह सड़कें, चौराहों, गोल चक्करों, उद्यानों में चटक रंग की रंग बिरंगी देशी-विदेशी फूलों, फूलदार झाड़ियों, छायादार और फूलदार वृक्ष दिखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज देश की राजधानी दिल्ली को इको-टूरिज्म हब बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दिल्ली में पहला विश्व स्तरीय नर्सरी तैयार करने का आदेश दिया है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को राष्ट्रीय अशोक विहार में स्थित खोजा वाला बाग में 25 एकड़ के भूखंड को एक सप्ताह में समतल कर विश्व स्तरीय नर्सरी बनाने का आदेश दिया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल के साथ डीडीए के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार, एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती सहित कई विभागों के वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इको-टूरिज्म हब बनाने के लिए डीडीए को दिल्ली में पहली विश्व स्तरीय नर्सरी तैयार करने का आदेश दिया।

बंजर भूमि पर उगाए जाएंगे फूल और पौधे

अशोक विहार में पीएमएवाई के तहत डीडीए की जेलर वाला बाग 'इन-सीटू सलम पुनर्वास' परियोजना के ठीक बगल में स्थित डीडीए द्वारा निर्मित इस 25 एकड़ के नर्सरी में सरकारी स्थानीय निकायों, सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ दिल्ली की जनता के उपयोग के लिए भी यहां पौधे उपलब्ध होंगे। इस नर्सरी में स्वदेशी, औषधीय गुण वाले देशी व विदेशी पौधों के अलावा फूलों, फलदार व फूलदार देशी विदेशी पौधे, फूलदार झाड़ियों के अलग-अलग किस्में लगाई जाएंगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि प्रस्तावित नर्सरी न केवल शहर की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए ऑक्सीजन 'हब' भी बनेगा। आस-पास के नागरिकों और आगंतुकों के लिए पर्यावरण पर्यटन के लिए यह नर्सरी भविष्य में पसंदीदा स्थान के रूप में उभरेगी। अशोक विहार, वजीरपुर, शालीमार बाग, आजादपुर और उत्तरी दिल्ली की अन्य आवासीय कॉलोनियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन स्थल के रूप में भी काम करेगा। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में विकसित होने के कारण, यह हरा पैच अब तक प्रदूषित पड़ोस के बहुत आवश्यक ऑक्सीजन युक्त फेफड़ों को स्वस्थ करने का काम करेगा।

कल्पतरु के अंतर्गत 40 लाख पौधों का वृक्षारोपण करेगी ब्रह्माकुमारी संस्था

नई दिल्ली | लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉरीशस की उच्चायुक्त एसबी हनुमानजी, मंगोलिया के राजदूत गणबोल्ड डंबजाव के साथ करुणा और दया का संदेश देते हुए ब्रह्माकुमारी संस्था के द्वारा देश भर में कल्पतरु थीम के अंतर्गत 40 लाख से अधिक पौधे लगाने के लिए कल्पतरु थीम सांग को शुरुआत की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने ब्रह्माकुमारी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बीके बृजमोहन एवं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी के साथ एक एप को भी लांच किया और इस अभियान का शुभारंभ भी किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER पंजाब केसरी 29 मई, 2022 ---DATED---

कायाकल्प की योजना : एलजी ने अशोक विहार स्थित खोजा वाला बाग का किया दौरा, दिए योजना की रूपरेखा बनाने के निर्देश

डीडीए बनायेगा विश्वस्तरीय नर्सरी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): नये पद की जिम्मेदारी संभालते ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना राजधानी के विकास एवं कायाकल्प के लिए आगे बढ़कर सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को खोजा वाला बाग अशोक विहार में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन का निरीक्षण किया। यहां डीडीए की 25 एकड़ खाली जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी तैयार की जाएगी। यहां बनने वाली नर्सरी में न सिर्फ देसी-विदेशी पौधों को तैयार किया जाएगा, बल्कि इसे राजधानी में ईको-टूरिज्म का बड़ा केन्द्र भी बनाया जाएगा। एलजी वीके सक्सेना अधिकारियों के साथ लगातार राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने शनिवार को अशोक विहार क्षेत्र में डीडीए की खाली जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां विश्वस्तरीय नर्सरी और ईको टूरिज्म हब तैयार करने के निर्देश दिए। एलजी ने एक सप्ताह के भीतर डीडीए को इस पूरी योजना की रूपरेखा तैयार करने को कहा। नर्सरी में स्थानीय प्रजाति के साथ-साथ विदेशी और दुर्लभ किस्म के पौधे भी तैयार किए जाएंगे। जिन्हें सरकारी विभागों के साथ आम नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। नर्सरी में कैफेटेरिया और गैलरी पथ भी बनाया जाएगा, ताकि लोग यहां पर सुकूनभरा वक्त बिता सकें। पर्यटन के लिहाज से भी इसे एक आकर्षक जगह के तौर पर तैयार किया जाएगा। नर्सरी के लिए चुनी गई यह जगह वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसलिए इस पूरी जगह को हरा-भरा बनाने से लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन भी मिल सकेगी। इससे लोगों को कुछ हद तक प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान एमसीडी के विशेष अधिकारी, डीडीए उपाध्यक्ष, निगम आयुक्त व अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।

अधिकारियों के साथ चर्चा करते उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना।

डीडीए की जमीन का निरीक्षण किया गया।

एलजी के दौरे के बाद हरकत में आया एमसीडी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किए जा रहे दौरे को देख दिल्ली नगर निगम ने सफाई अभियान को तेज कर दिया है। शनिवार को निगम के सफाई कर्मचारी सड़कों पर दिखाई दिए, वहीं अधिकारी भी मौके पर रहे। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते दो दिनों में सफाई-व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने निगम को फटकार लगाई है। फटकार के बाद निगम ने सफाई को और बेहतर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को नजफगढ़ जोन ने पीरा गढ़ी से महिपालपुर तक और द्वारका रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सड़कों की सफाई करने के साथ आसपास के क्षेत्रों में झाड़ियां भी हटाईं। वहीं अन्य अधिकारी ने बताया कि निगम के सभी 12 जोन में सफाई अभियान को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के स्पेशल ऑफिसर ने आदेश दिया है कि सफाई अभियान को और तेज किया जाए, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकें। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण को और तेज किया जाए।

पर्यटन का केन्द्र बनेगी नर्सरी

अधिकारियों ने बताया कि यह नर्सरी न केवल शहर की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य और व्यापक संसाधन पूल के रूप में काम करेगी, बल्कि इससे दिल्ली के लोगों और आगंतुकों के लिए पर्यावरण पर्यटन के लिए एक मनोरंजक गंतव्य के रूप में भी काम करेगी। साथ ही इससे आसपास भूमि के क्षरण को रोकने, भूमि के अतिक्रमण की जांच करने और एक हरित स्थान बनाने सहायता मिलेगी।

मिलेगी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत डीडीए की जेलर वाला बाग 'इन-सीटू स्लम पुनर्वास' परियोजना के ठीक बगल में स्थित यह नर्सरी न केवल सबसे वंचित वर्गों को पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरणीय अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि अशोक विहार, वजीरपुर, शालीमार बाग, आजादपुर और उत्तरी दिल्ली की अन्य आवासीय कॉलोनियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन स्थल के रूप में काम करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DATED 30-05-2022

बदहाली.... मधु विहार बस स्टैंड के पास गड्ढे की चपेट में आकर बाइक सवार की हो चुकी है मौत

द्वारकाः खतरनाक गड्ढे मौत को दे रहे दावत

दक्षिणी दिल्ली, (पंजाब केसरी) : एशिया की सबसे बड़ी उपनगरी द्वारका की मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। आलम यह है कि यहां आए दिन लोगों के वाहन गड्ढे में पड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। इससे लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।

कुछ माह पहले ही एक बाइक सवार की गड्ढे के कारण मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद डीडीए के अधिकारी सुस्त बैठे हुए हैं। द्वारका के कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मंगलापुरी को लिखित में दे चुके हैं। आरोप है कि डीडीए ने द्वारका की मुख्य सड़कों को कई सालों से नहीं बनाया है। इस कारण वह जर्जर हो चुकी हैं। यहां तक की द्वारका में ऐसी कोई सड़कें नहीं है जहां गड्ढे न हुए हों। लोगों का आरोप है कि रोड नंबर 201 की सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। एक साल से इन सड़कों पर गड्ढे हैं, लेकिन डीडीए ने इन सड़कों को बनवाना तो दूर गड्ढे तक को भरवाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। द्वारका उपनगरी को बसे लगभग तीस साल हो गए हैं। यहां की रोड नंबर 201 की सड़क मुख्य मार्ग है। यह सड़क दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, एयरपोर्ट व अन्य मुख्य मार्गों को जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इस सड़कों को लोग दिल्ली देहात नजफगढ़ व कई गांवों समेत हरियाणा जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ प्रमुख अपार्टमेंट, कई निजी स्कूल, मॉल्स, औद्योगिक क्षेत्र, डीडीयू कॉलेज व सरकारी दफ्तर भी हैं। ये सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अकसर इसके चपेट में आकर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डेढ़ माह पहले मधु विहार बस स्टैंड के पास एक बाइक सवार की गड्ढे के चपेट में आने से मौत तक हो चुकी है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मधु विहार द्वारका के अध्यक्ष रणबीर सिंह सोलंकी ने बताया कि जर्जर सड़क और गड्ढे को मरम्मत कराने को लेकर वह कई बार डीडीए के चीफ इंजीनियर को पत्र लिख चुके हैं। बावजूद मरम्मत नहीं कराई गई है। आंखों के सामने वह कई बार बाइक व स्कूटी सवार को गिरते हुए देखा है। उन्होंने डीडीए से मांग की है कि वह जल्द इन सड़कों और गड्ढों को मरम्मत कर दें, ताकि लोगों की जान बच सके।

▸▸ द्वारका की मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है।

द्वारका की सड़कें और गड्ढों से संबंधित समस्याओं की सूचना मेरे संज्ञान में है। इन समस्याओं से संबंधित अधिकारी को बता दिया जाएगा।

-संजय खरे, चीफ इंजीनियर, डीडीए

संबंधित अधिकारी से नहीं हुआ संपर्क

डीडीए द्वारका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीके जैन द्वारका की सड़कें और गड्ढों का काम देखते हैं। इस बाबत जब उनसे फोन पर संपर्क किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ था।

28 अगस्त तक पंजीकृत करा सकेंगे जमीन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अब किसान आगामी 28 अगस्त तक अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन को डीडीए के पास पंजीकृत करा सकेंगे। डीडीए ने शनिवार को लैंड पूलिंग पोर्टल को तीन महीने के लिए एक बार फिर खोल दिया। लैंड पूलिंग नीति में कुछ बदलाव के बाद इसे फिर खोला गया है। फरवरी में पोर्टल को बंद कर दिया गया था। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2018 को लैंड पूलिंग नीति की अधिसूचना जारी की थी। शुरुआती दौर में कुछ गांवों की जमीन को शहरी ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा न होने के कारण इसके दायरे में नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में कुल 109 सेक्टरों में विभाजित कर इस योजना को छह जोन में बांट दिया गया। योजना के तहत दिल्ली में 17 लाख आवास बनाए जाने हैं। जोन पी टू में सेक्टर दो व तीन, जोन एन में सेक्टर 10 और जोन एल में सेक्टर तीन में जल्द किसानों के सशर्त समूह बनाए जाएंगे। डीडीए ने विशेष पोर्टल भी बनाया है जिसके जरिये भू-स्वामी अपने दस्तावेज अथवा आवेदन संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। योजना में जोन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-2 में आने वाले 104 गांव शामिल हैं। यह पूरा क्षेत्र 129 सेक्टरों में विभाजित है।